

प्रेषक,

विनय शंकर पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उप सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन ।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग-1

देहरादून:

दिनांक 19 जुलाई, 2017

विषय:- सचिवालय परिसर में विश्वकर्मा भवन व बहुमंजिले भवन के चतुर्थ तल को जोड़ने हेतु 13.25 मी० स्पॉन के लौह सेतु के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रभारी मुख्य अभियन्ता, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, 162 ओल्ड नेहरू कालोनी (धर्मपुर) देहरादून के पत्रांक:-2062/78 भवन-स्तर-1(क्षे०का०) 2017 दिनांक 22.06.2017 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए आगणन धनराशि ₹ 31.53 लाख के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिवालय परिसर में विश्वकर्मा भवन व बहुमंजिले भवन के चतुर्थ तल को जोड़ने हेतु 13.25 मी० स्पॉन के लौह सेतु के निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग की विभागीय टी०ए०सी० के परीक्षणोपरान्त संस्तुत ₹ 31.53 लाख (₹ इकतीस लाख, तिरेपन हजार मात्र) के कम में वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि ₹ 31.53 लाख (₹ इकतीस लाख, तिरेपन हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-507/xxxii(1)/01(एक)-01/2017-18, दिनांक 11 अप्रैल 2018 एवं अलोटमेंट आई डी-H1704070002, दिनांक 05 अप्रैल 2017 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गई धनराशि में से प्रथम किश्त स्वरूप धनराशि ₹ 15.00 लाख (₹ पन्द्रह लाख मात्र) को व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि ₹ 31.53 लाख (₹ इकतीस लाख, तिरेपन हजार मात्र) का निम्न शर्तों के अधीन नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे ।

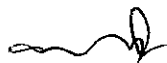
- (1) वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही प्रश्नगत कार्य तत्काल प्रारम्भ करा लिया जायेगा ।
- (2) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी ।
- (3) आगणन में प्राविधान/दर/मात्रा/धनराशि तथा विवरण आदि किसी भी प्रकार के अन्तर/पुनरावृत्ति के लिए विभागीय टी०ए०सी० तथा विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे ।



(2)

- (4) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- (5) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (6) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
- (7) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगी।
- (8) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
- (9) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या-2047/XXXIV-219(2006), दि० 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (10) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2008 में प्राविधानित नियमों एवं दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाय।
- (11) कार्यदायी संस्था द्वारा स्थापित किये जाने वाले सामग्री की वास्तविक लागत एवं जीवन अवधि सहित सूचना/विवरण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुमानित लागत एवं वास्तविक लागत के अन्तर स्वरूप जो धनराशि बचती है, उसे राजकोष में जमा किया जाय।
- (12) कार्यदायी संस्था द्वारा संतोषजनक/संतुष्टिपरक/गुणवत्ता पूर्वक कार्य किये जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (13) प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य समय से पूर्ण एवं गुणवत्ता हेतु समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (14) यदि कार्यो हेतु धनराशि की पुनरावृत्ति की गई होगी तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
- (15) आवासीय/अनावासीय भवनों में अनुरक्षण/मरम्मत/निर्माण कार्यो हेतु एक रजिस्टर बनाया जाय जिसमें किये गये कार्यो को अंकित किया जाय।
- (16) उक्त कार्य हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (17) आयकर की कटौती संबंधित अनुरक्षण इकाई द्वारा अपने स्तर से करायी जायेगी।
- (18) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे तथा आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा एवं कार्य समय से पूर्ण करा लिया जायेगा।

3. उप सचिव/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन द्वारा धनराशि ₹ 15.00 लाख (₹ पन्द्रह लाख मात्र) को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून के भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा-देहरादून के खाता संख्या-डी0सी0एल0 01 G 03099751-42, 10901749521, आई.एफ.एस.सी. कोड संख्या-SBIN0000630, में नियमानुसार जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। पैन्/टैन न०-MRTSO 1692F है।



(3)

4. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय-02 शहरी आवास-800-अन्य भवन-03-राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-70 मतदेय/xxvII(5)/2017-18, दिनांक 12 जुलाई, 2017 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनय शंकर पाण्डेय)

अपर सचिव।

संख्या-829/xxxii(1)-2017/01(दो)(160)/निर्माण/2017

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला।
- 3- प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग देहरादून।
- 4- मुख्य अभियन्ता, स्तर-II, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, 162 नेहरू कालोनी (धर्मपुर) देहरादून।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, 9वाँ एवं 11 वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग देहरादून।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून।
- 7- मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग देहरादून को इस निर्देश के साथ कि एन.आई.सी. में अपलोड करायें।
- 8- वित्त अनुभाग-5/नियोजन विभाग/बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- सचिवालय प्रशासन लेखा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- निदेशक एन.आई.सी. सचिवालय परिसर।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)

संयुक्त सचिव।

5